भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2744 का उत्तर

दो रेल उपरिपुलों का निर्माण

2744. श्री देवेश शाक्य:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कासगंज-अमांपुर मार्ग पर दो रेल उपरि पुलों के निर्माण की मांग पर अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का भविष्य में एटा और कासगंज जिलों को दिल्ली से जोड़ने का विचार है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): भारतीय रेल पर समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुल संबंधी कार्यों को स्वीकृत करना सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों को रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा, रेलगाड़ियों की गतिशीलता तथा सड़क उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव और व्यवहार्यता आदि पर इसके प्रभाव के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है और इन्हें शुरू किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-24 की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या
2004-14	4,148 अदद
2014-24	11,945 (लगभग तीन गुना)

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल पर 92,692 करोड़ रुपए की लागत से 4,200 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुल स्वीकृत है, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य में 13,502 करोड़ रुपए की लागत पर ऊपरी/निचले सड़क पुल के 741 अदद स्वीकृत कार्य हैं, जो योजना और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। 2014-24 के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 1,490 अदद ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया था।

कासगंज-अमनपुर सड़क दो समपारों के रास्ते से गुजरती है, अर्थात बरेली सिटी-कासगंज खंड के बीच किमी 420/9-421/0 पर समपार संख्या 309/ए तथा फर्रुखाबाद-कासगंज खंड के बीच किमी 244/1-2 पर समपार संख्या 248ए/स्पेशल।

इन समपारों पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ख): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृत/निष्पादित क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, न कि राज्य-वार/जिला-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्य/जिला की सीमाओं के पार फैली हुई होती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात के अनुमानों, अंतिम स्थान संपर्कता, मिसिंग लिंक और वैकल्पिक मार्गों, भीड़-भाड़ वाली संतृप्त लाइनों में बढ़ोतरी, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक महत्व आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

कासगंज पहले से ही मौजूदा रेल नेटवर्क द्वारा हाथरस जंक्शन के रास्ते दिल्ली से जुड़ा हुआ है और एटा पहले से ही मौजूदा रेल नेटवर्क द्वारा बुरहान जंक्शन के रास्ते दिल्ली से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, 2023-24 में 389 करोड़ रुपए की लागत पर एटा-कासगंज नई रेल लाइन परियोजना (29 कि.मी.) को मंजूरी दी गई है। परियोजना को "विशेष रेलवे परियोजना" घोषित किया गया है।

*****